कुरुक्षेत्र

भारतीय एम.एस.एम.ई. को पुनर्जीवित करना

संदर्भ

- केंद्रीय बजट 2025-26 में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) को आर्थिक परिवर्तन के केंद्र में रखना भारत के विकास पथ में एक महत्त्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है।

भारतीय एम.एस.एम.ई. एवं रोज़गार

- कृषि, निर्यात और निजी निवेश के साथ-साथ चार महत्त्वपूर्ण स्तंभों में से एक के रूप में पहचाने जाने वाले एम.एस.एम.ई. भारत के औद्योगिक और रोज़गार परिदृश्य के लिए महत्त्वपूर्ण हैं।
- वित्त वर्ष 2023-24 में 6.3 करोड़ से अधिक पंजीकृत उद्यमों में 25 करोड़ से अधिक लोगों को रोज़गार मिला हुआ है और भारत के कुल निर्यात में 45.73% का योगदान है। एम.एस.एम.ई. कृषि के बाद दूसरे सबसे बड़े रोज़गार सृजक हैं व विकेंद्रीकृत औद्योगीकरण में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं।

संशोधित वर्गीकरण

- बजट में एक प्रमुख सुधार एम.एस.एम.ई. वर्गीकरण सीमा का ऊपर की ओर संशोधन है। सूक्ष्म उद्यम अब ₹2.5 करोड़ तक निवेश कर सकते हैं एवं टर्नओवर सीमा बढ़ाकर ₹10 करोड़ कर दी गई है।
- छोटे उद्यम ₹100 करोड़ तक के टर्नओवर के साथ ₹25 करोड़ तक निवेश कर सकते हैं, जबकि मध्यम उद्यम ₹125 करोड़ तक निवेश और ₹500 करोड़ तक टर्नओवर कर सकते हैं।

- निवेश में 2.5 गुना वृद्धि और टर्नओवर सीमा में 2 गुना वृद्धि उद्यमों को वित्तीय और संस्थागत लाभ खोए बिना स्केल करने में मदद करने के लिए डिज़ाइन की गई है, जिससे औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र में छिपे हुए अंतर को पाटा जा सके।

क्रेडिट सशक्तीकरण : वित्तीय पहुँच को मज़बूत करना

- सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (CGTMSE) के विस्तार के माध्यम से क्रेडिट पहुँच को पर्याप्त बढ़ावा मिला है।
- सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी कवर को ₹5 करोड़ से बढ़ाकर ₹10 करोड़ कर दिया गया है, जिससे पाँच वर्षों में ₹1.5 लाख करोड़ का ऋण प्राप्त होगा।
- नवाचार-संचालित स्टार्टअप के लिए, 27 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में ऋण के लिए कम शुल्क के साथ गारंटी कैप को बढ़ाकर ₹20 करोड़ कर दिया गया है।
- निर्यातोन्मुख एम.एस.एम.ई. अब मज़बूत गारंटी व्यवस्था के तहत 20 करोड़ रुपए तक के टर्म लोन प्राप्त कर सकते हैं जिससे भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मक क्षमता बढ़ेगी।
- इसके अतिरिक्त, उद्यम-पंजीकृत सूक्ष्म इकाइयों के लिए एक अनुकूलित एम.एस.एम.ई. क्रेडिट कार्ड की शुरुआत (5 लाख रुपए तक का क्रेडिट समर्थन) डिजिटलीकृत, संपार्श्विक-मुक्त कार्यशील पूंजी तक पहुँच की सुविधा प्रदान करेगा, जिसमें पहले वर्ष में 10 लाख कार्ड जारी किए जाएंगे।

स्टार्टअप और समावेशी उद्यमिता को बढ़ावा

- ज़मीनी स्तर पर नवाचार और समावेशी विकास को प्रोत्साहित करने के लिए बजट में विभिन्न क्षेत्रों, विशेष रूप से टियर-2 और टियर-3 शहरों में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए 10,000 करोड़ रुपए के फंड ऑफ फंड का प्रस्ताव है।

- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं और ग्रामीण युवाओं के 5 लाख पहली बार उद्यमियों के लिए एक समर्पित योजना अगले पाँच वर्षों में 2 करोड़ रुपए तक के टर्म लोन की पेशकश करेगी जिसमें प्रारंभिक निवेश पूंजी, ब्याज अनुदान, तकनीकी सलाह और संस्थागत संपर्क के रूप में अतिरिक्त सहायता शामिल होगी।
- ये उपाय स्टैंड-अप इंडिया पहल पर आधारित हैं और इनका उद्देश्य सामाजिक व भौगोलिक सीमाओं के पार उद्यमशीलता का लोकतंत्रीकरण करना है।

श्रम-प्रधान क्षेत्रों को लक्षित करना : रोज़गार और निर्यात

- रोज़गार-प्रधान उद्योगों पर ध्यान केंद्रित करते हुए बजट में जूते, चमड़ा और खिलौने जैसे क्षेत्रों को आधुनिक बनाने व वैश्विक बनाने के लिए योजनाएँ पेश की गई हैं।
- जूते और चमड़ा उद्योग के लिए फोकस उत्पाद योजना में डिज़ाइन नवाचार, घटक निर्माण और गैर-चमड़ा क्षेत्र में विस्तार पर ज़ोर दिया गया है, जिससे 22 लाख नौकरियाँ पैदा होने और 4 लाख करोड़ रुपए का कारोबार होने की उम्मीद है।
- इसी तरह, खिलौना क्षेत्र को क्लस्टर विकास, आधुनिकीकरण और कौशल निर्माण के लिए समर्पित समर्थन प्राप्त होगा, जिससे भारत एक वैश्विक खिलौना केंद्र के रूप में स्थापित होगा।
- बिहार में एक राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान भी स्थापित किया जाएगा, जिसका उद्देश्य पूर्वी भारत में खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना है।

विनिर्माण व स्वच्छ तकनीक : भविष्य की तैयारी

- नए लॉन्च किए गए राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन के तहत एम.एस.एम.ई. को व्यापक औद्योगिक मूल्य शृंखलाओं में एकीकृत करने के लिए नीतिगत समर्थन व क्षेत्र-विशिष्ट रणनीतियाँ प्राप्त होंगी।

- स्वच्छ प्रौद्योगिकी विनिर्माण पर विशेष ज़ोर दिया गया है, जिसमें सौर पी.वी. सेल, ई.वी. बैटरी, पवन टरबाइन और उच्च-वोल्टेज ट्रांसमिशन उपकरणों के घरेलू उत्पादन के लिए प्रोत्साहन शामिल हैं।
- ये हस्तक्षेप भारत के हरित विकास लक्ष्यों के अनुरूप हैं और इनका उद्देश्य एम.एस.एम.ई. को वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण में प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित करना, आयात निर्भरता को कम करना और दीर्घकालिक औद्योगिक लचीलापन बढ़ाना है।

सतत् राजकोषीय प्रतिबद्धता : बजटीय सहायता

- बजट में एम.एस.एम.ई. मंत्रालय को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ₹23,168.15 करोड़ आवंटित किए गए हैं, जो वित्त वर्ष 2024-25 में ₹22,137.95 करोड़ से मामूली वृद्धि है।
- जबकि पिछले वर्षों में उतार-चढ़ाव देखा गया था- जैसे कि वर्ष 2024-25 के संशोधित अनुमान में ₹17,306.70 करोड़ की गिरावट और वर्ष 2022-23 में ₹23,628.73 करोड़ के शिखर तक पहुँचना। इस वर्ष का आवंटन लगातार नीति समर्थन को रेखांकित करता है।
- महत्त्वपूर्ण रूप से इस क्षेत्र का सकल मूल्य वर्द्धित (GVA) वर्ष 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद के 27.3% से बढ़कर वर्ष 2022-23 में 30.1% हो गया, जो बढ़ते आर्थिक लचीलेपन और प्रभाव का संकेत देता है।

निर्यात-आधारित विकास और वैश्विक एकीकरण

- एम.एस.एम.ई. भारत के निर्यात प्रदर्शन में एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरे हैं। उनका निर्यात वर्ष 2020-21 में ₹3.95 लाख करोड़ से बढ़कर वर्ष 2024-25 में ₹12.39 लाख करोड़ हो गया, इसी अवधि में निर्यात करने वाले एम.एस.एम.ई. की संख्या 52,849 से बढ़कर 1,73,350 हो गई।

- इस क्षेत्र का निर्यात हिस्सा भी वर्ष 2022-23 में 43.59% से बढ़कर वर्ष 2024-25 (मई 2024 तक) में 45.79% हो गया। इस उछाल को व्यापार सुविधा, डिजिटल मार्केटप्लेस और उत्पाद मानकीकरण द्वारा समर्थित किया गया है, जो एम.एस.एम.ई. को भारत की वैश्विक व्यापार महत्त्वाकांक्षाओं के साथ जोड़ता है।

निष्कर्ष

- भारत के एम.एस.एम.ई. केवल आर्थिक विकास में भागीदार नहीं हैं, वे समावेशी, टिकाऊ और वैश्विक रूप से एकीकृत विकास के उत्प्रेरक हैं। वर्ष 2025-26 का बजट विभिन्न क्षेत्रों और भौगोलिक क्षेत्रों में एम.एस.एम.ई. के लिए पैमाने, प्रतिस्पर्द्धात्मकता और पहुँच को मज़बूत करके एक परिवर्तनकारी रोडमैप निर्धारित करता है। जैसे-जैसे भारत अपने 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है, एम.एस.एम.ई. रोज़गार सृजन, नवाचार और औद्योगिक विकेंद्रीकरण के लिए केंद्रीय बने रहेंगे।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी द्वारा सशक्त एम.एस.एम.ई.

एम.एस.एम.ई. का महत्त्व

- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) भारत में आर्थिक विकास, रोज़गार सृजन, निर्यात योगदान, ग्रामीण विकास और समावेशी विकास के लिए महत्त्वपूर्ण हैं।
- वे आय के समान वितरण को सक्षम करते हैं और विशेष रूप से ग्रामीण व अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में आजीविका के अवसर प्रदान करते हैं।
- सार्वजनिक रूप से वित्तपोषित अनुसंधान और विकास को व्यवहार्य उत्पादों व प्रक्रियाओं में परिवर्तित करने के लिए एम.एस.एम.ई. को वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति के साथ एकीकृत करने की बढ़ती आवश्यकता है।

एम.एस.एम.ई. के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप

- सरकारी योजनाएँ एम.एस.एम.ई. को अनुसंधान, नवाचार और प्रौद्योगिकी में संसाधन प्रदान करती हैं, जिससे उनकी वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मकता और मान्यता बढ़ती है।
- एम.एस.एम.ई. ऊर्जा-कुशल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक बाइक, ड्रोन तकनीक, स्वास्थ्य सेवा उपकरण और क्लीनटेक जैसे क्षेत्रों में स्वदेशी तकनीकी नवाचार के केंद्र के रूप में उभर रहे हैं।

प्रमुख विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पहल

सामान्य अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी विकास केंद्र (CRTDH)

- वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग (DSIR) द्वारा वर्ष 2014-15 में शुरू किया गया CRTDH, उद्योग, शिक्षा और सरकार को जोड़कर एम.एस.एम.ई. क्लस्टरों में नवाचार को बढ़ावा देता है। यह शोध एवं विकास सुविधाएँ, परीक्षण प्रयोगशालाएँ, डिज़ाइन केंद्र, पायलट प्लांट और प्रोटोटाइप विकास प्रदान करता है।
- वर्तमान में, 18 CRTDH इलेक्ट्रॉनिक्स, नवीकरणीय ऊर्जा, किफायती स्वास्थ्य सेवा, पर्यावरण प्रौद्योगिकी और उन्नत सामग्री सहित क्षेत्रों में काम करते हैं, जो नवाचार और व्यावसायीकरण के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

MSME के लिए CSIR मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स

- CSIR द्वारा जनवरी 2025 में मुंबई में एम.एस.एम.ई. के लिए स्थापित किया गया CSIR मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स, विश्व स्तरीय इनक्यूबेशन लैब, तकनीकी सहायता, वैज्ञानिक बुनियादी ढाँचा और नेटवर्किंग स्थान प्रदान करता है।

- यह उन्नत वैज्ञानिक विशेषज्ञता और व्यवसाय विकास सेवाएँ प्रदान करते हुए एम.एस.एम.ई., स्टार्टअप, CSIR प्रयोगशालाओं, डीप-टेक फर्मों और सार्वजनिक अनुसंधान संस्थानों के बीच सहयोग की सुविधा प्रदान करता है।

निधि-प्रौद्योगिकी व्यवसाय इनक्यूबेटर (निधि-टी.बी.आई.) कार्यक्रम

- इसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा निधि कार्यव्रम के तहत लॉन्च किया गया था। यह शैक्षणिक और शोध संस्थानों में इनक्यूबेटरों के माध्यम से उच्च जोखिम वाले, उच्च क्षमता वाले तकनीकी स्टार्टअप का समर्थन करता है।
- यह स्टार्टअप को नवाचारों का तेज़ी से व्यावसायीकरण करने और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप रोज़गार सृजित करने में मदद करने के लिए बुनियादी ढाँचा, सलाह, कानूनी, वित्तीय और आई.पी. परामर्श प्रदान करता है।

निधि-समावेशी प्रौद्योगिकी व्यवसाय इनक्यूबेटर (निधि- आई.टी.बी. आई.)

- निधि-आई.टी.बी.आई. उभरते स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्रों में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देता है। इसमें ग्रामीण, टियर-2 और टियर-3 शहरों पर ध्यान केंद्रित कर सामाजिक समावेशन पर ज़ोर दिया जाता है, जैसे- महिलाएँ, भौगोलिक विविधता और दिव्यांग व्यक्ति।
- यह शिक्षाविदों, निवेशकों और उद्योग को जोड़ने वाले स्थानीय नवाचार नेटवर्क का निर्माण करते हुए अवधारणा के प्रमाण, प्रोटोटाइप और प्रारंभिक चरण के विकास के लिए अनुदान प्रदान करता है।

प्रौद्योगिकी के माध्यम से ग्रामीण उद्यम त्वरण केंद्र (CREATE)

- लेह में स्थापित CREATE, लद्दाख जैसे चुनौतीपूर्ण इलाकों में पश्मीना ऊन, आवश्यक तेलों और जैव-प्रसंस्करण जैसे स्थानीय उत्पादों के लिए प्रशिक्षण और विकास प्रदान करके ग्रामीण औद्योगीकरण व एम.एस.एम.ई. विकास को बढ़ावा देता है, जिसका उद्देश्य दूरदराज़ के क्षेत्रों में उत्पादकता, गुणवत्ता, आर्थिक क्षमता और आजीविका में सुधार करना है।

प्रौद्योगिकी विकास केंद्रों का विस्तार

- एम.एस.एम.ई. मंत्रालय विभिन्न क्षेत्रों में 33 प्रौद्योगिकी विकास केंद्र चलाता है जो डिज़ाइन, विनिर्माण, कौशल विकास और उन्नत प्रौद्योगिकियों तक पहुँच में एम.एस.एम.ई. की सहायता करता है।
- जॉब वर्क, सटीक उत्पादन और विशेष उपकरण निर्माण जैसी सेवाओं की पेशकश करते हुए पहुँच का विस्तार करने के लिए बिल्ड-ऑपरेट-ट्रांसफर (BOT) PPP मॉडल के तहत नए केंद्र विकसित किए जा रहे हैं।

नए प्रौद्योगिकी केंद्रों और विस्तार केंद्रों के लिए योजना

- इसका उद्देश्य हब-एंड-स्पोक मॉडल पर 20 प्रौद्योगिकी केंद्र और 100 विस्तार केंद्र स्थापित करना है जो AI, AR, VR, IoT और रोबोटिक्स जैसी उन्नत तकनीकों को ज़मीनी व दूरदराज़ के क्षेत्रों में पहुँचाएगा।
- अब तक 25 विस्तार केंद्र चालू किए जा चुके हैं, जिनमें 72,000 से अधिक प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण दिया गया है और 1,440 एम.एस.एम.ई. को सहायता प्रदान की गई है।

निष्कर्ष

- विज्ञान और प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप एम.एस.एम.ई. की प्रतिस्पर्द्धात्मकता, नवाचार और वैश्विक मान्यता को बढ़ा रहे हैं, जिससे एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र विकसित हो रहा है जो नवाचार, रोज़गार, ग्रामीण उत्थान व समावेशी विकास को बढ़ावा देता है। नतीजतन, एम.एस.एम.ई. क्षेत्र बुनियादी आर्थिक इकाइयों से नवाचार केंद्रों और भारत की अर्थव्यवस्था में सतत् विकास के प्रमुख चालकों के रूप में विकसित हो रहा है।